



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2019/आषाढ़ 7, 1941

No. 177]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2019/ASHADHA 7, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

मामला सं. ओ.आई. – 09/2019

विषय: चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “नाइलोन मल्टी फिलामेंट यार्न” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए याचिका।

फा. सं. 6/11/2019-डीजीटीआर.—मै. गुजरात पॉली फिल्म्स लिमिटेड और मै. सेंचुरी एंका लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे ‘याचिकाकर्ता’ कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाइलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “नाइलोन मल्टी फिलामेंट यार्न” (जिसे यहां आगे संबद्ध सामान अथवा विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया।

क. विचाराधीन उत्पाद

1. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) “नायलोन का सिथेटिक फिलामेंट यार्न” है जिसे “पालीमाइड यार्न” अथवा “नाइलोन मल्टी फिलामेंट यार्न” के रूप में भी जाना जाता है।
2. विचाराधीन उत्पाद में फ्लैट यार्न- ट्रिवस्टेड और/अथवा अनटिवस्टेड, पूरी तरह से ड्रॉन यार्न (एफ डी वाई), स्पिन ड्रॉन यार्न (एस डी वाई) पूरी तरह से ऑरिएंटेड यार्न (एफ ओ वाई), हाई ऑरिएंटेड यार्न (एच ओ वाई), आंशिक रूप से ऑरिएंटेड यार्न (पीओवाई), टैक्सचर्ड यार्न- ट्रिवस्टेड और/अथवा अनटिवस्टेड तथा डाइड यार्न, सिंगल, डबल,

मल्टीपल, फोल्डेट अथवा केवल्ड जैसे नाइलोन अथवा पोलीमाइक्रोफिलामेंट यार्न की सभी किस्में शामिल हैं। नाइलोन फिलामेंट यार्न ऑर्गेनिक मोनोमर्स के पोलीमराइजेशन से उत्पादित सिंथेटिक फिलामेंट यार्न होता है। विचाराधीन उत्पाद में केवल मल्टीफिलामेंट यार्न शामिल होता है और मोनोफिलामेंट यार्न इस क्षेत्र से अलग किए जाते हैं। मल्टी फिलामेंट यार्न होने के नाते मदर यार्न को भी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जाता है।

3. संबद्ध सामान एच एस कोड 5402 31, 5402 32, 5402 39, 5402 45, 5402 49, 5402 51, 5402 59, 5402 61 और 5402 69. के तहत सीमाशुल्क शीर्ष 5402 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
4. इस उत्पाद में फ्लैट/टैक्सचर्ड/टिवस्टेड/अनटिवस्टेड ब्राइट/सेमीडल/फुल डल (अथवा उनके विभिन्न रूप), ग्रे/कलर्ड/डाइड (अथवा उनके विभिन्न रूप), सिंगल/डबल/मल्टीपल/फोल्डेट/केवल्ड (अथवा उनके विभिन्न रूप), आकार के हों अथवा नहीं, जैसे नाइलोन फिलामेंट यार्न अथवा पालीमाइक्रोफिलामेंट यार्न की सभी किस्में शामिल हैं परंतु नाइलोन का हाईटेनासिटी यार्न शामिल नहीं होता है। सभी मानव निर्मित फिलामेंट यार्न, जिनमें नाइलोन अथवा पालीमाइक्रोफिलामेंट यार्न नहीं है, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है।
5. याचिकाकर्ताओं ने क्रिम्प्ड/फ्लैट यार्न, आंशिक रूप से ओरिएटेड/पूरी तरह से ड्रॉन यार्न, फिलामेंट, डेनियर, लस्टर और कलर के आधार पर पी सी एन सिद्धांत का सुझाव दिया है। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त होने के बाद तथा जांच प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर विदेशी उत्पादकों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों के बीच उचित तुलना के लिए अंतिम पी सी एन का निर्णय लेंगे हितबद्ध पक्षकार सूचना दायर कर सकते हैं और इस संबंध में उचित अनुरोध कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

6. याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान समान वस्तु हैं। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित नाइलोन फिलामेंट यार्न और संबद्ध देशों से निर्यातित नाइलोन फिलामेंट यार्न में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित नाइलोन फिलामेंट यार्न भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित सामानों को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

7. वर्तमान याचिका मैसर्स गुजरात पॉली फिल्म्स लिमिटेड और मै. सेंचुरी एंका लिमिटेड द्वारा दायर की गई है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके उत्पादन का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। याचिका के लिए एक समर्थन पत्र मै. प्रफुल्ल ओवरसीज प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि भारत में कई उत्पादकों ने संबद्ध सामानों का आयात किया है। याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक और उन उत्पादकों को हटाने के बाद लगभग 60 प्रतिशत है जो अपने आप में तथाकथित पाटित उत्पाद के आयातक हैं। याचिकाकर्ताओं ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातिक अथवा आयातक अथवा भारत में विचाराधीन के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।
8. अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि जिस याचिकाकर्ता का वर्तमान में कुल घरेलू उत्पादन का "प्रमुख अनुपात" है वह नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

घ. शामिल देश

9. वर्तमान जांच चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाइलैंड से विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन के संबंध में है।

ड. सामान्य मूल्य

10. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार किया है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य पर विचार किया है। कोरिया जन.गण., ताइवान और थाइलैंड के मामले में इन आधारों पर निर्मित सामान्य मूल्य के संबंध में दावा किया है कि कीमत से संबंधित सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है। निर्मित सामान्य मूल्य का निर्धारण संबद्ध देशों में विद्यमान विद्युत दरों और प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार करके किया गया है। प्राधिकारी ने जांच के प्रयोजन के लिए इसे उपयुक्त और पर्याप्त माना है।

च. निर्यात कीमत

11. याचिकाकर्ताओं ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत की गणना की है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और सामान्य मानदंडों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा के निर्मित कीमत संबंधी समायोजन किए गए हैं।

छ. पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के संबंध में काफी सकारात्मक पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात कीमत से अधिक हैं जो प्रथम दृष्टया ये दर्शते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातिकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है।

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क

13. याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने पूर्ण दृष्टि से और भारत में उत्पादन तथा खपत, कीमत न्यूनीकरण, कम कीमत पर विक्री के संबंध में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। पाटनरोधी जांच की शुरूआत का औचित्य बनाने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही “क्षति” का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

14. और जबकि प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन; घरेलू उद्योग को क्षति और पाटनरोधी जांच की शुरूआत का औचित्य बनाने के लिए तथाकथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के पर्याप्त साक्ष्य पाटनरोधी जांच की शुरूआत का औचित्य बनाने के लिए विद्यमान हैं, प्राधिकारी एतद्वारा तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को “क्षति” समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार घरेलू उद्योग को तथाकथित पाटन और परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं।

ज. जांच की अवधि (पी ओ आई)

15. याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान जांच अप्रैल, 2018 से दिसंबर, 2018 (9 माह) तक प्रस्तावित की है। तथापि, प्राधिकारी 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक 12 माह लेते हुए जांच की अवधि पर विचार करना उपयुक्त मानते हैं। क्षति जांच की अवधि में 2015-16, 2016-17, 2017-18 और जांच की अवधि शामिल होगी।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों के निर्यातिकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार और संबंधित तथा घरेलू उद्योग के लिए ज्ञात भारत में प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए तथा निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने ज्ञात विचार देने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:

महानिदेशक

व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

- 17 कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार निम्नलिखित निर्धारित स्वरूप और तरीके से अपने जांच से संगत अनुरोध कर सकते हैं। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराएं।

ट. समय सीमा

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए ताकि वह प्राधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भी हालत में दिन 40 दिन से अनधिक तक उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाए। यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) के भीतर घेरेलू उद्योग के आवेदन पत्र पर अपनी टिप्पणियां दें। यह सूचना हार्ड कॉपी तथा साफ्ट कॉपी में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ठ. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्टों/ उनसे संबद्ध अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों के लिए यह अपेक्षित है कि यदि वे प्रश्नावली के किसी भाग के संबंध में “गोपनीयता” का दावा करते हैं तो वह दो अलग-अलग सैटों में दायर किया जाना अपेक्षित है।
21. “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी ऐसे अनुरोधों को देखने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रूपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के दो (02) सैटों में हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी होंगी।
22. गोपनीय रूपांतर में वे सभी सूचनाएं होंगी जो प्रकृति से गोपनीय हैं और/अथवा अन्य सूचना होगी, जिसे उस सूचना को देने वाला गोपनीय के रूप में दावा करे। जो सूचना प्रकृति में गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वह दी गई सूचना के साथ एक पुष्ट विवरण प्रदान करे कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
23. अगोपनीय रूपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचकांकन व्यवहार्य नहीं है) और सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त व्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवादम्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है और सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।
24. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु अनिच्छुक हैं तो वे उस सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
25. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता है।

26. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल की निरीक्षण

27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

ढ. असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में काफी वाधा ढालता है तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी जांच और केन्द्र सरकार को आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिश कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2019

(Case No. O. I.-09/2019)

Subject: Petition for initiation of anti-dumping investigations on the imports of “Nylon Multi Filament Yarn” originating in or exported from China PR, Korea RP, Taiwan and Thailand.

F. No. 6/11/2019-DGTR.—M/s. Gujarat Polyfilms Limited and M/s Century Enka Limited (hereinafter referred to as the “petitioners”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for imposition of Anti-dumping duty on imports of Nylon Multi Filament Yarn (hereinafter referred to as the “Product Under Consideration” or the “subject goods”) originating in or exported from China PR, Korea RP, Taiwan and Thailand (hereinafter referred to the “subject countries”).

A. Product Under Consideration

1. The product under consideration (PUC) in the present investigation is “Synthetic Filament Yarn of Nylon” also known as “Polyamide Yarns” or “Nylon Multi Filament Yarn”.
2. The product under consideration includes all kinds of synthetic filament yarns of Nylon or Polyamides, such as flat yarn - twisted and/or untwisted, Fully Drawn Yarn (FDY), Spin Drawn Yarn (SDY), Fully Oriented Yarn (FOY), High Oriented Yarn (HOY), Partially Oriented Yarn (POY), textured yarn – twisted and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled. Nylon filament yarn is a synthetic filament yarn produced by polymerization of organic monomers. The product under consideration includes only multi-filament yarn and Mono Filament Yarns are excluded from the scope. Mother yarn, being multi-filament yarn, is also included in the scope of product under consideration.
3. The subject goods are classified under customs heading 5402 under HS Codes 5402 31, 5402 32, 5402 39, 5402 45, 5402 49, 5402 51, 5402 59, 5402 61 and 5402 69. The Customs classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

4. The product includes all variants of Nylon Filament Yarn or Polyamide Yarns such as flat/textured/twisted/untwisted, bright/semi-dull/full-dull (or variants thereof), grey/colored/dyed (or variants thereof), single/double/ multiple/folded/cabled (or variants thereof), whether or not sized, but excludes high tenacity yarn of nylon. All man-made filament yarns not having nylon or polyamides are beyond the scope of the product under consideration.
5. The petitioners have suggested a PCN methodology based on crimped / flat yarn, partially oriented / fully drawn yarn, filaments, denier, luster and colour. However, the Designated Authority shall decide final PCNs for the purpose of fair comparison between the products produced by foreign producers and domestic industry after receipt of questionnaire response and on the basis of information and evidence provided by various interested parties during the course of investigation. The interested parties may file information and make appropriate submissions in this regard.

B. Like Article

6. The petitioners submitted that subject goods produced by the petitioner companies and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There are no known differences in nylon filament yarn produced by the Indian industry and that exported from the subject countries. Nylon filament yarn produced by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The goods produced by the petitioners should be treated as like articles to the product under consideration imported from the subject countries.

C. Domestic Industry and Standing

7. The present petition has been filed by M/s Gujarat Polyfilms Limited and M/s Century Enka Limited, claiming that their production constitutes a major proportion in Indian production. A support letter for the petition has been submitted by M/s Prafful Overseas Pvt. Ltd. The petitioners have submitted that many of the producers in India have imported the subject goods. Production of the petitioners constitutes more than 30% in gross Indian production and about 60% after excluding such producers who are themselves importer of the alleged dumped product. The petitioners have certified that they have not imported the subject goods and are not related to any exporter or importer of the PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.
8. The Authority, therefore, determines that the petitioner who presently holds a “major proportion” of the total domestic production, constitutes an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and also satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. Countries Involved

9. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR, Korea RP, Taiwan and Thailand.

E. Normal Value

10. The petitioners have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Para 7 of Annexure – I of the Rules. The Authority has *prima facie* considered the normal value of the subject goods on the basis of constructed normal value. Normal value in case of Korea PR, Taiwan and Thailand has been claimed on constructed cost basis on the grounds that information with regard to price is not available in public domain. The constructed normal value has been determined considering international price of major raw material and power rates prevailing in the subject countries. The Authority has considered the same as appropriate and sufficient for the purpose of initiation.

F. Export Price

11. The petitioners have computed the export price on the basis of data published by DGCI&S. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight as per the general norms.

G. Dumping Margin

12. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* show significant positive dumping margin in respect of the subject goods from the subject countries. There is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating *prima facie*, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

H. Injury and Causal Link

13. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling. There is sufficient *prima facie* evidence of the ‘injury’ being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

I. Initiation of Anti-Dumping Investigations

14. And whereas, the Authority *prima facie* finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

J. Period of Investigation (POI)

15. The petitioners have proposed a present investigation from April, 2018 to December, 2018 (9 months). However, the Authority considers it appropriate to consider a period of investigation covering 12 months from 1st April, 2018 to 31st March, 2019. The injury investigation period shall cover 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the period of investigation.

K. Submission of Information

16. The exporters in the subject countries, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Director General
 Directorate General of Trade Remedies,
 Jeevan Tara Building, 4th Floor
 5, Parliament Street, New Delhi -110001

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

L. Time Limit

18. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

-
19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

M. Submission of Information on Confidential Basis

20. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof.
21. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.
22. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
26. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

27. In terms of Rule 6(7) of the Anti-Dumping Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

O. Non-cooperation

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General